बनाती हैं, उनकी इम्पोर्ट बन्द कर दी जाती है, जिससे कन्ज्यूमर इम्पोर्ट नहीं कर सकता और उस को मजबूरन यहां पर चार गुनी या पांच गुनी कीमत देनी पड़ती है। इस सम्बन्ध में क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जहां तक कन्ज्यूमर इन्टरेस्ट का सवाल है, इस बात का बराबर ख्याल रखा जाता है। जहां तक कीमतों में अन्तर का सवाल है, उस के अलग अलग कारण हो सकते हैं—जिसकी विजहते अन्तर हो सकता है। जहां तक इम्पोर्ट बन्द करने का सवाल है, वह तो होना ही चाहिए, जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। इसी वजह से हमारी यह नीति है कि जो चीजें देश में पैदा होती हैं, उनकी इम्पोर्ट बन्द कर देनी चाहिये।

श्री प्रेम चन्द वर्मा: क्या यह सच नहीं है कि व्यूरो आफ़ पिल्लक एन्टरप्राइजेज इस वक्त केवल पोस्ट आफिस का काम कर कर रहा है। क्या सरकार इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिये, इस को फिर से रिओगेनाइज करने के लिये, इस को ज्यादा अख्तियार देने के लिये किसी कार्यवाही पर विचार करेगी?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यह कहा गया है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है।

NATIONAL INCOME

*815. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

- (a) the rate of growth of the National Income and per capita income during the first year of the Fourth Five Year Plan;
- (b) whether it is a fact that the growth has been far below the targets fixed in the draft outline of the Fourth Five Year Plan and also less than the achievements during the Third Five Year Plan; and
- (c) if so, the steps proposed to be taken to increase per capita income?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SIRI K. C. PANT): (a) The 'Quick Estimate' of national income for 1966-67 prepared by the Central Statistical Organisation shows an increase of 1.7 per cent in real terms over the preceding year. Due to the population increase, the per capita income, however, is estimated to show a decline of 0.7 per cent.

(b) and (c). The slow rate of growth in 1966-67, which was below the targets fixed in the draft outline of the Fourth Five Year Plan and also less than the achievements in the Third Plan, was primarily due to the continued drought conditions affecting agricultural and other production. The better harvests of 1967-68 are expected to result in a substantial increase in national and per capita income. Efforts will continue to be made to increase agricultural and other production further to secure further increases in per capita incomes.

श्री सीताराम केसरी: क्या यह सही है कि हमारे देश में पर-कैंपिटा इन्कम के गिरने का कारण मन्दी है ? क्या यह भी सत्य है कि विदेशों से जो सहायता आती थी, उस के अभाव के कारण आपने चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा को प्रस्तुत करने में विलम्ब किया है ? हमारी राष्ट्रीय इन्कम का पचास फीसदी कृषि से आता है—मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है, जिससे कि हमारे कृषि के उत्पादन बढ़ें ताकि उन के द्वारा हमारी आमदनी वह सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: उत्पादन बढ़ाने के लिये हर प्रकार की कोशिश हो रही है। जहां तक मन्दी का सवाल है, पर-कैपिटा इन्कम कम होने की वजह मन्दी नहीं है। मन्दी होने की वजह ही इन्कम में कमी है। जहां तक फोर्य प्लान का ताल्लुक है—जिन एजम्पशन्ज पर फोर्य प्लान बनाया गया था, उस में कई परिवर्तन हो गये—डिवैत्यूएशन के कारण सुखे के कारण दामों के बढ़ने

के कारण—इन सब बातों के कारण यह जरूरी हो गया कि चौथे प्लान को 1969 से शुरू किया जाय।

श्री सीताराम केसरी: क्या यह सच है नहीं है कि आपका वे-अनप्रोडिक्टव है। आप निर्माण में ज्यादा पैसा लगाते हैं, लेकिन प्रोडिक्टव निर्माण में कम लगाते हैं? क्या आप की कोई-कोई ऐसी योजना है कि जिस के द्वारा कृषि के उत्पादन में वृद्धि हो, उस पर आप ज्यादा खर्च करें, जिस से कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके।

श्री कृष्ण चन्त्र पंत : कोशिश तो बराबर हो रही है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने कहा है कि फसलों के अच्छी होने के कारण इस वर्ष प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी । मैं जानना चाहता हूं कि कितनी आय बढ़ने की सम्भावना है तथा इस आमदनी को देखते हुए वास्तव में कितनी होनी चाहिये ?

श्री कृष्ण चन्न पंत : इस समय जो है, वह मेंने बताया है कि 1.7 प्रतिशत है। लेकिन जो होने की सम्भावना है, उसके आंकड़े अभी देना ठीक नहीं है, जब तक कि अगली फसल आ न जाय। कुछ आंकड़े हम ने अनुमान किये हैं, लेकिन उन्हें अभी में नहीं देना चाहता हूं।

OIL EXPLORATION OF IRANIAN SHORE
+

*817. SHRI HIMATSINGKA: SHRI S. S. KOTHARI: SHRI SRINIBAS MISRA:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

- (a) whether the Oil and Natural Gas Commission in collaboration with ENI of Italy and Phillips of the U.S.A. have been successful in striking oil about 140 kilometres from the Iranian shore;
 - (b) the terms of collaboration;
- (c) the estimated annual yield of oil from this source, the Indian share

in this yield, and the amount spent so far in this venture; and

(d) whether further off-shore oil explorations are being carried out in the Persian Gulf, and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMIAH):

(a) Yes, Sir.

- (b) Attention is invited to the statement placed on the Table of the Lok Sabha in reply to Starred Question No. 142 answered on 24-2-1965 which contains the terms of the agreement.
- (c) It is too early to indicate the annual yield of oil from this source. ONGC's share will be 1/6 of the annual production and there is an obligation to buy 1/6 more from the NIOC, if asked. The total expenditure incurred by the Commission up to the end of October, 1967 amounts to Rs. 13.11 crores approximately.
- (d) Further exploratory drilling is contemplated. Details have not yet been settled.

SHRI HIMATSINGKA: What is the share of the Oil and Natural Gas Commission, payable to the first party, namely, the Iranian Oil Company? What is the share of income?

SHRI RAGHU RAMAIAH: So far as exploration is concerned, the second party only pays and we have to pay one-third of it. So far as commercial production is concerned, it is fifty-fifty.

SHRI S. S. KOTHARI: How much is the internal demand for oil in excess of the available supply, how much oil is at present imported and to what extent will imports be reduced on account of the success of this yenture?

SHRI RAGHU RAMAIAH: I have already stated this. It is very difficult to say at this stage what would be the actual amount of oil which will be available on account of this